Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 15–2026] CHANDIGARH, THURSDAY, APRIL 9, 2026 (CHAITRA 19, 1948 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

उद्योग और वाणिज्य विभाग

शुद्धिपत्र

दिनांक 20 मार्च, 2026

सं. 02/03/2025–1IB–II.— हरियाणा के राज्यपाल 'हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति, 2020' के अनुच्छेद संख्या–14.14 और हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति, 2020' में अधिसूचित 16 प्रोत्साहन योजनाओं के विभिन्न उप–अनुच्छेदों के अंतर्गत हर्षपूर्वक नीचे उल्लिखित शुद्धिपत्र जारी करते हैं ;

एच.ई.ई.पी.–2020 के अनुच्छेद संख्या 14.14 में संशोधनः

क्रम सं.	नीति का नाम	वर्तमान धारा	संशोधित धारा
1	हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति, 2020' अधिसूचना सं. 25/05/2020-4IB-I, दिनांक 29.12.2020	**धारा 14.14** "14.14 अल्ट्रा और मेगा प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स और माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए उपलब्ध इंसेंटिव की डिटेल्स एनेक्सर-4 में दी गई हैं। हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना के तहत, ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में ग्रामीण इलाके में स्थापित माइक्रो एंटरप्राइजेज को इंसेंटिव लेने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से **एन.ओ.सी./ सी.एल.यू.** जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस पॉलिसी के तहत इंसेंटिव उन इंडस्ट्रीज़ को नहीं मिलेंगे जो इंडस्ट्रीज़ की रिस्ट्रिक्टिव लिस्ट (एनेक्सर-5) में शामिल हैं, सिवाय स्टेट एक्सपोर्ट अवार्ड्स और स्टेट अवार्ड्स के। सरकार बदले हुए हालात के हिसाब से इस लिस्ट में कभी भी बदलाव कर सकती है"।	अल्ट्रा एवं मेगा परियोजनाओं, बड़ी परियोजनाओं तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु उपलब्ध प्रोत्साहनों का विवरण परिशिष्ट-4 में दिया गया है। हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से **एन.ओ.सी./ सी.एल.यू.** प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा| राज्य निर्यात पुरस्कार एवं राज्य पुरस्कार को छोड़कर नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रतिबंधित उद्योगों की सूची (परिशिष्ट-5) में सम्मिलित उद्योगों को उपलब्ध नहीं होंगे, सरकार परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार इस सूची में किसी भी समय संशोधन कर सकती है। इसके अलावा**, एन.ओ.सी./ सी.एल.यू.** छूट कम से कम 50 उद्यमियों की मौजूदा यूनिट्स पर भी लागू होगी, जिनकी यूनिट्स कम से कम 10 एकड़ की लगातार ज़मीन पर हैं, और जो 1/1/2021 से पहले कमर्शियल प्रोडक्शन में आ गई हैं, यह छूट निम्नलिखित योजनाओं के तहत लागू होती है: 1. प्रौद्योगिकी अधिग्रहण सहायता 2. लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र हेतु एस.एम.ई. एक्सचेंज इक्विटी योजना 3. परीक्षण उपकरण सहायता योजना

			4. बाजार विकास सहायता योजना 5. पेटेंट पंजीकरण योजना 6. ऊर्जा संरक्षण योजना 7. जल संरक्षण योजना 8. गुणवत्ता प्रमाणन सहायता योजना 9. नेट एस.जी.एस.टी. के बदले निवेश सब्सिडी 10. क्रेडिट रेटिंग योजना 11. सुरक्षा अनुपालन योजना 12. अनुसंधान एवं विकास केंद्र योजना 13. कोलेटरल-फ्री क्रेडिट गारंटी 14. प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु राज्य क्रेडिट लिंक्ड ब्याज सब्सिडी 15. मालभाड़ा सहायता योजना 16. अवसंरचना औद्योगिक विकास योजना

नीचे दी गई 16 प्रोत्साहन योजनाओं के उप–अनुच्छेदों में बदलाव ;

क्र.सं.	**योजना**	**अधिसूचना संख्या**	**वर्तमान धारा**	**संशोधित धारा**
1	प्रौद्योगिकी अधिग्रहण सहायता	सं.02/03/2023-1IB-II दिनांक 21.04.2023	**एन.ओ.सी./ सी.एल.यू.धारा** 5 (vi)	सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार टीसीपी/ यूएलबी अथवा सक्षम प्राधिकारी से **एन.ओ.सी./ सी.एल.यू. / अस्थायी छूट/ नियमितीकरण प्रमाण-पत्र।**
2	लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र हेतु एस.एम.ई.एक्सचेंज इक्विटी योजना	सं.25/05/2020-4IB-I दिनांक 08.06.2021	**एन.ओ.सी./ सी.एल.यू.धारा** 4 (iii) & 17 (iv)	
3	परीक्षण उपकरण सहायता योजना	सं.25/05/2020-4IB-I दिनांक 08.06.2021	**एन.ओ.सी./ सी.एल.यू.धारा** 5 (iii)	
4	बाजार विकास सहायता योजना	सं.25/05/2020-4IB-I दिनांक 08.06.2021	**एन.ओ.सी./ सी.एल.यू.धारा** 4 (iii) & 16 (vii)	
5	पेटेंट पंजीकरण योजना	सं.25/05/2020-4IB-I दिनांक 08.06.2021	**एन.ओ.सी./ सी.एल.यू.धारा** 4 (iii) & 31 (iv)	
6	ऊर्जा संरक्षण योजना	सं.25/05/2020-4IB-I दिनांक 08.06.2021 & सं.02/02/2023-1IB-II दिनांक 20.04.2023	**एन.ओ.सी./ सी.एल.यू.धारा** 5 (vi) & 27 (iv)	
7	जल संरक्षण योजना	सं.25/05/2020-4IB-I दिनांक 08.06.2021	**एन.ओ.सी./ सी.एल.यू.धारा** 5 (vi) & 21 (iv)	
8	गुणवत्ता प्रमाणन सहायता योजना	सं.25/05/2020-4IB-I दिनांक 08.06.2021	**एन.ओ.सी./ सी.एल.यू.धारा** 5 (iii) & 14 (v)	
9	नेट एस.जी.एस.टी.के बदले निवेश सब्सिडी	सं.25/05/2020-4IB-I. दिनांक 29.07.2021	**एन.ओ.सी./ सी.एल.यू.धारा** 4.a. (v)	
10	क्रेडिट रेटिंग योजना	सं.25/05/2020-4IB-I दिनांक 08.06.2021	**एन.ओ.सी./ सी.एल.यू.धारा** 4 (iii) & 13 (iv)	
11	सुरक्षा अनुपालन योजना	सं.25/05/2020-4IB-I दिनांक 08.06.2021	**एन.ओ.सी./ सी.एल.यू.धारा** 5 (iv) & 19 (iv)	
12	अनुसंधान एवं विकास केंद्र योजना	सं.25/05/2020-4IB-I दिनांक 08.06.2021	**एन.ओ.सी./ सी.एल.यू.धारा** 4(ii) &13 (iv)	
13	कोलेटरल-फ्री क्रेडिट गारंटी	सं.25/05/2020-4IB-I दिनांक 04.10.2021	**एन.ओ.सी./ सी.एल.यू.धारा** 5. vi (c)	
14	प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु राज्य क्रेडिट लिंक्ड ब्याज सब्सिडी	सं.25/05/2020-4IB-I दिनांक 04.10.2021	**एन.ओ.सी./ सी.एल.यू.धारा** 5 (v) & 17 (iv)	
15	मालभाड़ा सहायता योजना	सं.25/05/2020-4IB-I दिनांक 08.06.2021 & सं.02/07/2023-1IB-II दिनांक 26.07.2023	**एन.ओ.सी./ सी.एल.यू.धारा 14 (viii) और अधिसूचना संख्या 02/07/2023-1IB-II दिनांक 26.07.2023 की धारा 14 (x)**	

16	अवसंरचना औद्योगिक विकास योजना	सं.25/05/2020-4IB-I दिनांक 11.10.2021	**एन.ओ.सी./ सी.एल.यू.धारा** 6(i)	

नोटः– "टी. सी. पी. विभाग के पोर्टल पर अस्थायी छूट या नियमितीकरण प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन करते समय हर आवेदन–पत्र पर ₹25 प्रति वर्ग मीटर की स्क्रूटनी फीस लगेगी।"

परिभाषाएँ :

एन.ओ.सी./सी.एल.यू. छूटः

एन.ओ.सी./सी.एल.यू. से छूट कम से कम 50 उद्यमियों की मौजूदा उन एम.एस.एम.ई. इकाइयों पर लागू होगी, जिनकी इकाईयाँ कम से कम 10 एकड़ की लगातार जमीन पर हैं, मिलकर नियमितीकरण के लिए एक पोर्टल पर आवेदन करती हैं और 01/01/2021 से पहले वाणिज्यिक उत्पादन में आ चुकी हैं।

नया सूक्ष्म उद्यमः

वह उद्यम जिसने 01.01.2021 के बाद और 31.12.2025 से पहले, प्लांट, मशीनरी या इक्विपमेंट में निवेश के रूप में कैपिटल खर्च किया है और वाणिज्यिक उत्पादन (पूंजी अनुदान के लिए) में आए हैं या जिसे सावधि ऋण (ब्याज अनुदान के लिए) मंजूर किया गया है। वह उद्यम जो नीति शुरू होने की तिथि यानी 01.01.2021 को या उसके बाद वाणिज्यिक उत्पादन में आए हैं ।

मौजूदा उद्यमः

वह उद्यम जो नीति के प्रारंभ होने की तिथि अर्थात 01.01.2021 से पहले वाणिज्यिक उत्पादन में चला गया है।

ऊपर बताए गए बदलावों के अनुसार, मौजूदा एम.एस.एम.ई. और औद्योगिक इकाईयाँ ऊपर बताई गई योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त के लिए योग्य होंगी।

[हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण सर्वोच्च होगा]

अमित कुमार अग्रवाल,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
उद्योग और वाणिज्य विभाग।

चंडीगढ़ :
दिनांक 20 मार्च, 2026

HARYANA GOVERNMENT

INDUSTRIES & COMMERCE DEPARTMENT

Corrigendum

The 20th March, 2026

No. 02/03/2025-1IB-II.— The Governor of Haryana is pleased to issue corrigendum under the 'Haryana Enterprises & Employment Policy, 2020', Clause No.14.14 and various sub-clauses in the respective 16 Nos. of incentive schemes notified under the Haryana Enterprises and Employment Policy (HEEP) 2020 as under:

Amendment in the Clause No. 14.14 of HEEP-2020:

Sr. No.	Name of the Policy	Existing Clause	Amended Clause
1.	Haryana Enterprises and Employment Policy (HEEP), 2020 Notification No. 25/05/2020-4IB-I dated 29.12.2020	**Clause 14.14** The details of incentives available for Ultra & Mega Projects, Large Projects and Micro, Small & Medium Enterprises have been given in the Annexure-4. The Micro Enterprises set up in rural area within the jurisdiction of Village Panchayat, under Haryana Gramin Udyogik Vikas Yojna, shall not be required to submit CLU/NOC from Town & Country Planning for availing	**Clause 14.14** The details of incentives available for Ultra & Mega Projects, Large Projects and Micro, Small & Medium Enterprises have been given in the Annexure-4. The Micro Enterprises set up in rural area within the jurisdiction of Village Panchayat, under Haryana Gramin Udyogik Vikas Yojna, shall not be required to submit CLU/NOC from Town & Country Planning for availing incentives. The incentives under the policy will not be available to the industries covered under the restrictive list of industries (Annexure-5) except State Export Awards and State Awards.

		incentives. The incentives under the policy will not be available to the industries covered under the restrictive list of industries (Annexure-5) except State Export Awards and State Awards. The Government may modify this list at any time depending upon the changed scenario."	The Government may modify this list at any time depending upon the changed scenario. Furthermore, the CLU/ NOC exemption shall also apply to the existing units of at least 50 entrepreneurs, whose units are located on at least 10 acres of contiguous land and have come into commercial production before 1/1/2021, exemption applies under the following schemes: • Technology Acquisition Assistance Scheme. • SME Exchange Equity Scheme for Small and Medium Enterprise Sector. • Testing Equipment Assistance Scheme. • Market Development Assistance Scheme. • Patent Registration Scheme. • Energy Conservation Scheme. • Water conservation Scheme. • Quality Certification Assistance Scheme. • Investment Subsidy in lieu of Net SGST. • Credit Rating Scheme. • Safety Compliance Scheme. • Research and Development Centre Scheme. • Collateral Free Credit Guarantee. • State Credit Linked Interest Subsidy for Technology Upgradation. • Freight Assistance Scheme. • Infrastructure Industrial Development Scheme.

Amendment in sub-clauses of the following 16 Nos. of Incentive Schemes:

Sr. No.	Schemes	Notification No.	Conditions & Clause No.	Amendment
1.	Assistance for Technology Acquisition Scheme	No. 02/03/2023-1IB-II dated 21.04.2023	NOC/CLU Clause 5 (vi)	NOC/CLU/ Provisional exemption / regularisation Certificate from TCP/ULB or Competent Authority as decided by the Government.
2.	SME Exchange Equity scheme for Small and Medium Enterprise Sector	No. 25/05/2020-4IB-I dated 08.06.2021	NOC/CLU Clause 4 (iii) & 17 (iv)	
3.	Testing Equipment Assistance Scheme	No. 25/05/2020-4IB-I dated 08.06.2021	NOC/CLU Clause 5 (iii)	
4.	Market Development Assistance Scheme	No.25/05/2020-4IB-I dated 08.06.2021	NOC/CLU Clause 4 (iii) & 16 (vii)	
5.	Patent Registration Scheme	No. 25/05/2020-4IB-I dated 08.06.2021	NOC/CLU Clause 4 (iii) & 31 (iv)	
6.	Energy Conservation Scheme	No.25/05/2020-4IB-I dated 08.06.2021 & No.02/02/2023-1IB-II dated 20.04.2023	NOC/CLU Clause 5 (vi) & 27 (iv)	
7.	Water Conservation Scheme	No.25/05/2020-4IB-I dated 08.06.2021	NOC/CLU Clause 5 (vi) & 21 (iv)	
8.	Quality Certification Assistance Scheme	No. 25/05/2020-4IB-I dated 08.06.2021	NOC/CLU Clause 5 (iii) & 14 (v)	

Sr. No.	Schemes	Notification No.	Conditions & Clause No.	Amendment
9.	Investment Subsidy in lieu of Net SGST	No. 25/05/2020-4IB-I dated 29.07.2021	NOC/CLU Clause 4.a. (v)	
10.	Credit Rating Scheme	No. 25/05/2020-4IB-I dated 08.06.2021	NOC/CLU Clause 4 (iii) & 13 (iv)	
11.	Safety Compliance Scheme	No. 25/05/2020-4IB-I dated 08.06.2021	NOC/CLU Clause 5 (iv) & 19 (iv)	
12.	Research and Development Centre Scheme	No. 25/05/2020-4IB-I dated 08.06.2021	NOC/CLU Clause 4(ii) &13 (iv)	
13.	Collateral Free Credit Guarantee	No.25/05/2020-4IB-I dated 04.10.2021	NOC/CLU Clause 5 vi (c)	
14.	State Credit Linked Interest Subsidy for Technology Upgradation	No.25/05/2020-4IB-I dated 04.10.2021	NOC/CLU Clause 5 (v) & 17 (iv)	
15.	Freight Assistance Scheme	No.25/05/2020-4IB-I dated 08.06.2021 & No.02/07/2023-1IB-II dated 26.07.2023	NOC/CLU Clause 14 (viii) and Clause 14 (x) of notification No. 02/07/2023-1IB-II dated 26.07.2023	
16.	Infrastructure Industrial Development Scheme	No.25/05/2020-4IB-I dated 11.10.2021	NOC/CLU Clause 6(i)	

Note:- "A scrutiny fee of ₹25 per square metre shall be levied on each application while applying for provisional exemption or regularisation certificates on portal of the TCP Department."

Definitions:

Exemption for CLU/NOC:

The CLU/NOC exemption shall be applicable to the existing MSME units of at least 50 entrepreneurs, whose units are located on at least 10 acres of contiguous land, collectively apply on a portal for regularisation and have come into commercial production before 1/1/2021.

New Micro Enterprise:

The enterprise which has incurred capital expenditure in the form of investment in plant, machinery or equipment and gone into commercial production (for capital subsidy) or to which term loan has been sanctioned (for interest subsidy) after 01.01.2021 and before 31.12.2025. The Enterprise which has gone into commercial production on or after date of commencement of the Policy i.e. 01.01.2021.

Existing Enterprise:

The Enterprise which has gone into commercial production before date of commencement of the Policy i.e. 01.01.2021.

The existing MSMEs and industrial units will be eligible to avail benefits under the aforementioned schemes, in accordance with above mentioned amendments.

[In case of any discrepancy between the Hindi and English versions, the English version shall prevail.]

AMIT KUMAR AGRAWAL,
Commissioner & Secretary to Government Haryana,
Industries and Commerce Department.

Chandigarh:
The 20th March, 2026

12518—C.S.—H.G.P., Pkl.